भारत सरकार
इस्पात मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 405
2 दिसंबर, 2025 को उत्तर के लिए

इस्पात विनिर्माताओं हेतु पीएलआई योजना और सहायता

405. डॉ. दग्गुबाती पुरंदेश्वरीः
क्या **इस्पात** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विशेष गुणता के इस्पात के लिए उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना की स्थिति क्या है और इसमें कितना निवेश आकर्षित हुआ है;

(ख) द्वितीयक इस्पात उत्पादकों (जैसे टीएमटी बार रोलिंग मिलों) को सहायता प्रदान करने के संबंध में सरकार की नीति क्या है;

(ग) राजामुन्दरी निर्वाचन क्षेत्र में और इसके आस-पास इस्पात रोलिंग मिलों तथा टीएमटी बार विनिर्माताओं की संख्या कितनी है;

(घ) राजामुन्दरी में इन इकाइयों के लिए प्रतिस्पर्धी कीमतों पर कच्चे माल (जैसे स्क्रैप या बिलेट) की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(ड.) इन स्थानीय इस्पात इकाइयों को आधुनिकीकरण और हरित प्रौद्योगिकी को अपनाने में सहायता करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

उत्तर

इस्पात राज्य मंत्री (श्री भूपतिराजु श्रीनिवास वर्मा)

(क) विशेष इस्पात के लिए उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना को जुलाई 2021 में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा ₹6,322 करोड़ के बजट के साथ अनुमोदित किया गया था, जिसका उद्देश्य वित्तीय प्रोत्साहनों के माध्यम से विशेष इस्पात के उत्पादन को बढ़ावा देना है। अक्टूबर 2025 तक, सहभागी लाभार्थी कंपनियों ने ₹23,022 करोड़ का निवेश किया है।

(ख) से (घ): इस्पात एक नियंत्रणमुक्त क्षेत्र है, और सरकार इस्पात क्षेत्र के विकास के लिए अनुकूल नीतिगत वातावरण तैयार करके सुविधा प्रदाता की भूमिका निभाती है। निवेश, क्षमता वृद्धि, रोजगार, उत्पाद पोर्टफोलियो आदि से जुड़े निर्णय कंपनियों द्वारा प्रौद्यो-वाणिज्यिक विश्लेषण के आधार पर लिए जाते हैं। वर्ष 2024-25 में, ईस्ट गोदावरी और विशाखापत्तनम में राजमुंदरी चुनाव क्षेत्र और उसके आस-पास क्रमशः 2 और 9 इस्पात रोलिंग मिलें थीं। इस्पात स्क्रैप पुनर्चक्रण नीति, 2019 विभिन्न मंत्रालयों के साथ समन्वय के लिए एक ढांचा प्रदान करती है ताकि विभिन्न स्रोतों से उत्पन्न होने वाले लौह स्क्रैप के पुनर्चक्रण को बढ़ावा दिया जा सके।

(ङ) इस्पात मंत्रालय, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत इस्पात क्षेत्र में हाइड्रोजन के उपयोग के लिए पायलट परियोजना लागू कर रहा है। इस मिशन के तहत अब तक इस्पात क्षेत्र में चार पायलट परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं। कच्चे माल जैसे स्क्रैप की उपलब्धता देश के इस्पात उद्योगों जिसमें राजमुंदरी क्षेत्र भी शामिल है को प्रतिस्पर्धी मूल्य पर सुनिश्चित करने के लिए मूल सीमा शुल्क की समय-समय पर समीक्षा की जाती है।

******